ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य

** अंजली सिंह और **डॉ. श्री. प्रकाश मिश्र ,*

**शोध-छात्रा (शिक्षाशास्त्र) एम.एल. के.पी. जी. कॉलेज बलरामपुर उत्तरप्रदेश*

***प्रोफेसर (बी.एड.विभाग) एम. एल. के. पी. कॉलेज बलरामपुर उत्तरप्रदेश*

सारतत्त्व:

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इंसान की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उस के व्यवहार में सुधार लाना है | शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन 1986 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी | इसमें सन 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। आज समय के साथ हमें यह महसूस हुआ कि 1986 की वह शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं इसके तहत बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा है किन्तु यह ज्ञान उससे भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नही बन पा रहा हैं | अतः इन कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी |

बीजशब्द: *राष्ट्रीयशिक्षा, सांस्कृतिकमूल्य,संज्ञानात्मक,क्षमता,नियम*

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial Use Provided the Original Author and Source Are Credited.

प्रस्तावना:

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आने वाले आवश्यकता को पूरा करना है | यह नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य, जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था उसके नियमों का वर्णन सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखता है | राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है | यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए |राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ज्ञानार्जन को दिव्य ज्ञान की कोटि तक पहुँचाने का संकल्प लेकर

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

निर्मित है। इसके परिचय भाग के प्रारंभ में ही यह लिखा है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा से सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना गया है। इन लक्ष्यों के समन्वय से शिक्षा का कार्य अंतर्तम को प्रकाशित करना बन जाता है। अर्थात व्यक्ति को अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'। यहाँ प्रकाशित होने का मूल तात्पर्य है मानवीय आत्मा को अच्छाई की ओर ले जाना तथा उसे एक श्रेष्ठतम व्यक्ति बनाना।

इसी तथ्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में व्यक्त किया गया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञानार्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। ज्ञानार्जन शिक्षा का मुख्य ध्येय है। भारतीय शास्त्रों में एक शब्द आता है-'दिव्य ज्ञान'। इसका भावार्थ है कि शिक्षा के माध्यम से प्रदत्त एवं प्राप्त दिव्य ज्ञान जो मात्र ज्ञान दान नहीं है, इससे कहीं ऊपर है और इसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने समग्र शिक्षा का विकास कहकर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की दृष्टि से विचार किया है। समग्र शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जिससे शिक्षार्थी में संस्कार और सुरुचि का पल्लवन और पोषण किया गया हो, जीवन जीने का ढंग सिखाया गया हो, जो विनयदात्री हो- विद्या ददाति विनयम और जो मनुष्य को पूर्ण मनुष्यत्व की ओर ले जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

29 जुलाई 2020 को **कस्तूरी रंगन** की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाई गई। यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल है। इस समिति ने **मई 2019** में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था। **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020'**वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।वर्ष 2030 तक इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने की आशा है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है।

- NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।
- तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

- इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
- कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंज़ूरी दी गई है।
- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन
- 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी / बालवाटिका/ प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण "प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा" की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समग्र शिक्षा:

समग्र शिक्षा' के विकास का अर्थ है विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ पर जोर देना न कि 'रटंत विद्या' पर, जिससे कि रचनात्मकता और तार्किक सोच की क्षमता शिक्षार्थी में पैदा की जा सके। साथ ही यह नई शिक्षा नीति समग्र शिक्षा के विकासक्रम के लिए नैतिकता एवं मानवीयता के भारतीय मूलाधारों को भी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रारूप में सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना का विवेचन ही नहीं, विद्यार्थी के समग्र विकास में इनके योगदान को भी भिन्न-भिन्न स्थलों पर रेखांकित किया गया है। शिक्षार्थी में बहुआयामी मेधा का विस्तार करने के लिए शिक्षा नीति के प्रारूप में संगीत, स्वच्छता, व्यायाम और योगाभ्यास आदि का भी समावेश गया है। ये मेधाएँ स्वतः अपने आप में रचनात्मक भी हैं और मूल्यपरक भी। जिस रचनात्मकता के विकास की बात इस नीति में कही गई है उसका उद्देश्य है विद्यार्थी की सहज जिज्ञासा को प्रोत्साहन देना और इस जिज्ञासा के माध्यम से उसकी संवेदन शक्ति तथा प्रत्यक्षीकरण की प्रतिभा को विकसित करना। नवीन शिक्षा नीति में इस बात का बार-बार उल्लेख किया गया है कि सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्रियाओं द्वारा शिक्षार्थी की कल्पनाशक्ति को उर्वर बनाया जा सकता है। इस उर्वरता को फलीभूत करने की प्रक्रिया में ज्ञान को थोपना नहीं अपितु उसे क्रियाशील बनाकर शिक्षार्थी में ऐसी चेतना का विकास करना है कि उसके भाषायी कौशल, प्रकृति बोध, नैतिकता का भाव और सामाजिकता की मेधा

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

स्वतः अपना आकार लेने लगे। शिक्षाशास्त्र में इस समन्वित शैक्षिक गतिविधि को '**समग्र अवलोकन विधि**' कहा गया है और इन्हें भिन्न-भिन्न शैक्षिक धरातलों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में समाविष्ट किया गया है।

वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास:

सहानुभूति का पक्ष अंततः भारतीय चिंतन के केंद्रबिंदु सूत्र '**वसुधैव कुटुंबकम**' तक विस्तार पाता है। इसी से विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़े रहकर विश्व नागरिक बन सकेगा। सहानुभूति की भावना का विकास व्यक्ति से शुरू होकर विश्व तक की एकात्मकता तक विस्तीर्ण हो जाता है। हम मिलकर चलें (संगच्छध्वम) और मिलकर बोलें (संवदध्वम) का विचार ही परस्पर प्रेम की भावना का प्रसार कर देता है। इससे एकता और संगठन का भाव भी प्रबल होता है।भारतीय ज्ञान परंपरा का यह दृढ़ विश्वास है कि स्व-अनुशासन के माध्यम से ही स्वाभिमान जागृत होता है। स्व-अनुशासन जब 'निजता की पहचान' करवाता है तो आत्म-गौरव स्वतः जागृत हो उठता है। यही आत्मविश्वास मनुष्य को आत्मनिर्भरता के विविध सोपानों की ओर अग्रसर करता है। 'आत्मनिर्भर भारत' के महती लक्ष्य की प्राप्ति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक सुचिंतित प्रारूप है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में यह माना गया है कि शिक्षा संस्कृति का ही एक अनिवार्य अंग है। हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ मूल्यवान प्रदान करती है। शिक्षा नीति का बल इसीलिए अनौपचारिक शिक्षा पर भी है और वाचिक परंपरा पर भी। यह दो ध्रुवों को साधनेवाली नीति है जो 'परंपरा की शिक्षा' और 'शिक्षा की परंपरा' दोनों को साथ लेकर चलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विषयगत शिक्षा तथा बोधपरक शिक्षा:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विषयगत शिक्षा तथा बोधपरक शिक्षा के निहित भेदों को पहचानते हुए एक संतुलित प्रारूप का निर्माण किया है। बोधपरक शिक्षा का अर्थ है विद्यार्थी में स्वाध्याय, स्वचिंतन और स्वविवेक का विकास करना। इस संबंध में ध्यातव्य है कि हममें से अधिकांश के लिए शिक्षा का अर्थ यह सीखना है कि **'हम क्या सोचें'।** जबकि शिक्षा का अर्थ होना चाहिए कि हमें 'कैसे सोचना चाहिए'। यही वास्तव में 'सम्यक शिक्षा' है जो हमें जीवंत मानव बनाती है।यह अखिल भारतीय शिक्षा समागम काशी में हो रहा है इसलिए ध्यातव्य कि **महामना मदनमोहन मालवीय** ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के ज्ञान, मातृभाषाओं के महत्व, साहित्य, धर्म और दर्शन की शिक्षा, कृषि और कला-कौशल की शिक्षा, आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति की शिक्षा तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं की शिक्षा को केंद्रीय स्थान दिया था। उनका मानना था कि हमारे व्यक्तित्व में अखंडता और पूर्णता तभी आ सकती है जब हम 'भारत' को जानें, समझें और उसे अपनी आत्मा का अभिन्न अंग बना लें। नई शिक्षा नीति 'भारतीय' होने का भावार्थ व्यक्त करती है। उसकी यह उद्घोषणा विचारणीय है कि समग्र और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में रोपी गई हों वह 'विश्व के समक्ष भारतीय मेधा को अपनी आब और अस्मिता के साथ प्रस्तुत कर पाने का एकमात्र मार्ग है।'

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण:

- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- NEP-2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' IITI, 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' [National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit] स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मज़बूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन:

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' NCERT द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी।
- NEP-2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण सुधार किया गया है, इसमें मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिये जाएगा –
- 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट)
- 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा
- 3 वर्ष के बाद डिग्री
- 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकते हैं |
- नई शिक्षा नीति के तहत एम फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है |

उच्च शिक्षा आयोग: चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-

विनियमन हेतु- National Higher Education Regulatory Council- NHERC

मानक निर्धारण- General Education Council- GEC

वित पोषण- Higher Education Grants Council-HEGC

प्रत्यायन- National Accreditation Council- NAC

राष्ट्रीयशिक्षा नीति 2020 के पूर्व शैक्षणिक परिदृश्य: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से पूर्व भारत में 1986 की शिक्षा नीति संचालित थी जिसमें केवल किताबी बातों पर ध्यान दिया जाता था पुराने शिक्षा नीति में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था की स्कूल मैं कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अर्जित किया गया ज्ञान भविष्य में कैसे रोजगार सृजन में सहायक

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

होगा। पुराने शिक्षा नीति पाठ्यक्रम प्रधान थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता था। बचपन से ही बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने लिखने हेतु विवश किया जाता था, जिस कारण बच्चा अपनी मातृभाषा से अनभिज्ञ बना रहा। पहले उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान यदि किसी कारणवश बच्चा 1 या 2 साल बाद पढ़ाई बीच में छोड़ता था तो उसका नुकसान होता था।

1 या 2 वर्षों में उसने जो कुछ भी सीखा उसका कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता था जिसके कारण पुनः डिग्री करने के लिए उसे अपने साल बर्बाद करने पड़ते थे। पहले कंप्यूटर या तकनीकी ज्ञान का अभाव था, बच्चा उच्च शिक्षण संस्थानों में जाकर कोडिंग का ज्ञान लेता था किंतु अब छठी कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी।NEP-2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली/विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहले कॉलेज से 3 साल की डिग्री लेने के बाद 2 वर्ष स्नातकोत्तर और फिर 2 वर्ष का एमफिल उसके बाद 5 वर्ष पीएचडी करने के बाद शोध उपाधि प्राप्त हो पाती थी। किंतु अब एम फिल को समाप्त कर दिया है।

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम:

- नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ और जान पाएगा।
- इस नई नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर पाता है तो भी उसका नुकसान नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त हो पाएगा। जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा।
- छठी कक्षा से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी जिससे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, यानी बच्चे मात्र किताबी और व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं अपितु तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

कुल मिलाकर यह नीति बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी।

2020 में नई शिक्षा नीति 30 वर्षों के बाद आई और भारत की मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली को अकादमिक के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर बनाने के उद्देश्य से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2040 तक एनईपी की स्थापना करना है। लक्षित वर्ष तक, योजना का मुख्य बिंदु एक-एक करके लागू किया जाना है। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधार केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू होगा। कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर के मंत्रालयों

ISSN: P-2455-0515
E- 2394-8450

Educreator Research Journal

VOLUME–XI, ISSUE– I JAN – FEB 2024

Original Research Article

के साथ विषयवार समितियों का गठन किया जाएगा।

निष्कर्ष: यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी | इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें | इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे ; साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए | जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें |

संदर्भग्रन्थसूची:

1. चौबेसरयूप्रसाद 1959 'भारतीय शिक्षा का इतिहास'भवदीयप्रकाशनफ़ैजाबाद
2. गुप्ताडॉ.एस. पी. 1995 'भारतीयशिक्षाकाविकासएवंसमस्याएं'शारदापुस्तकभवन
3. भटनागरजे. सी. 2003 'अध्यापकशिक्षा'अग्रवालपब्लिकेशनआगरा
4. कुमारहेमंत 2006-07 'भारतमेंशिक्षाप्रगतिकाविकास'विनोदपब्लिकेशनआगरा
5. शर्माडॉ. एन. के. 2007'अध्यापकशिक्षा'के. एस. के.पब्लिशर्सएंडडिस्ट्रिब्यूटर्सनईदिल्ली
6. पाण्डेयरामसकल 2007 'उदीयमानभारतीयसमाजमेंशिक्षा'अग्रवालपब्लिकेशनआगरा
7. पाठकपी. डी. 2009 'भारतीयशिक्षाऔरउसकीसमस्याएं'विनोदपुस्तकमंदिरआगरा
8. गुप्ताएस. पी. अलकागुप्ता 2010 आधुनिकभारतीयशिक्षाकीसमस्याएंविनोदपुस्तकआगरा
9. लोढ़ाजितेंद्र 2013 आधुनिकभारतीयशिक्षाआरलालबुकडिपोआगरा
10.New education policy 2020 दस्तावेज

Cite This Article:
***सिंह अ. और डॉ. श्री. मिश्र प.* (2024).** *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य.* In Educreator Research Journal: Vol. XI (Number I, pp. 282–289). **ERJ.** https://doi.org/10.5281/zenodo.10730551